

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनु० - 1

देहरादून, दिनांक : 05 अप्रैल, 2005

विषय:-शासकीय निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय निर्माण कार्यो के संपादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के चयन/निर्धारण के सम्बन्ध में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्णय लिया गया है:-

शासकीय निर्माण कार्यो के लिए प्रदेश की निर्माण इकाईयों की तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता के आलोक में निर्माण एजेन्सियों के विस्तार पर रोक लगाने हेतु आवश्यक है कि राज्य के बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को उनके आगणन पर अब कोई भी नया निर्माण कार्य स्वीकृत न किया जाये। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के निर्माण कार्यो की क्षमता के दृष्टिगत इनसे अधिक निर्माण कार्य कराये जाय। साथ ही उत्तरांचल के राजकीय निगमों में प्रमुख रूप से उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को, जिन्हें सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु भी गठित किया गया है, से अधिक से अधिक निर्माण कार्य कराया जाये। गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की कार्य क्षमता को देखते हुए इनसे भी निर्माण कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत राजकीय निर्माण कार्यो हेतु उक्त निर्माण एजेन्सियों में से चयन के लिए निम्न निर्माण सिद्धान्तों/मापदण्डों का अनुपालन कराया जाय:-

(क) ₹0 200.00 लाख तक के सभी भवन निर्माण कार्य (मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवन) - उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरांचल राज्य के निगम एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कराये जा सकते हैं।

(ख) ₹0 200.00 लाख से अधिक एवं ₹0 800.00 लाख तक के (मानकीकृत भवन निर्माण कार्य) किसी भी निर्माण एजेन्सी से कराया जा सकता है, परन्तु राज्य के बाहर की निर्माण एजेन्सी को न्यूनतम टेंडर के आधार पर ही निर्माण कार्य आबंटित किये जाय।

(ग) ₹0 200.00 लाख से अधिक गैर मानकीकृत भवन निर्माण कार्य तथा ₹0 800.00 लाख से अधिक के समस्त भवन निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम से आगणन प्राप्त कर निविदा के माध्यम से प्रतियोगितात्मक

स्पर्धा के आधार पर कराया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम धनराशि का आंकलन निगम को देय सेन्टेज चार्ज को घटाकर किया जायेगा।

2. कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से एक स्थान पर प्रस्तावित समस्त निर्माण कार्य एक ही कार्यदायी संस्था से कराया जाये। यदि किसी कारणवश निर्माण कार्य एक कार्यदायी संस्था को देने से निर्धारित समयान्तर्गत निर्माण कार्य पूरा न कराया जा सके तो प्रशासनिक विभाग एक से अधिक कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु आवद्ध कर सकता है, परन्तु यह आवद्धता ऐसी होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक निर्माण इकाई को निर्माण कार्य पूरा करने में दूसरी निर्माण इकाई पर किंचित मात्र भी निर्भर न रहना पड़े।

3. निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया आंगणन पूरी तरह लोक निर्माण विभाग की दरों पर आधारित होना चाहिए। प्रतिवर्ष मानक दरों के निर्धारण हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल पेयजल निगम/मुख्य अभियन्ता की एक समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा निर्धारित मानक दरों की सूचना नियमित रूप से सभी सम्बन्धित को दी जायेगी।

4. मानकीकृत भवन की विशिष्टताएं लोक निर्माण विभाग द्वारा इन भवनों के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप प्रत्येक कार्यदायी संस्था द्वारा अपने आंगणन में समावेशित किया जाना होगा। यथासम्भव इन मानकीकृत भवनों के मानचित्र लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र पर ही आधारित होंगे।

5. निर्माण कार्य आवंटन के समय ही निर्धारित समय तथा लागत, जिसके अन्दर कार्य पूरा होना है, पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा तय कर लिया जाना चाहिए और तदनुसार निर्माण हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित प्रत्येक विभाग द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में जो निर्माण कार्य पूर्व में जिस कार्यदायी संस्था को आवंटित किया जा चुका है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन इस निर्णय के परिणाम स्वरूप नहीं किया जायेगा। केवल डेबिटेबिल कार्य की स्थिति उत्पन्न होने पर ही निर्माण दायी संस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। यथासम्भव स्वीकृत आंगणन के आधार पर तैयार किये गये विस्तृत आंगणन के अनुरूप ही पूर्व स्वीकृत निर्माण पूरे करा लिये जायें और उनमें किसी प्रकार का संशोधन केवल अपरिहार्य स्थिति में ही कराये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

6. उत्तरांचल के बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य टेण्डर के आधार पर दिए जायें एवं उत्तरांचल की कार्यदायी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाय।

7. समस्त निर्माण कार्य निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों द्वारा ही सभी निर्माण एजेंसियों द्वारा कराये जायेंगे। किसी भी दशा में आंगणन के आधार पर कार्य का सम्पादन नहीं कराया जायेगा।

8. संशोधित आगणन का पुनः संशोधित आगणन स्वीकार न किए जाय।

9. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के चयन संबंधी आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे, अर्थात् ऐसे मामले पुनरीक्षित नहीं किए जायेंगे, जहां कार्यदायी संस्था का पूर्व से निर्धारण हो चुका है।

10. विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य का अनुश्रवण भी अत्यन्त आवश्यक है। निर्माण कार्य कराने वाले सभी प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि उनके द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए जाय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा भी नोडल अधिकारी नामित किए जाय, जो निर्माण कार्य का संयुक्त रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर तुरन्त विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यथाशीघ्र भवन आदि विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सी से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित होगा। विभागीय सचिव के स्तर पर कम से कम प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समय से निर्माण कार्य पूरा किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

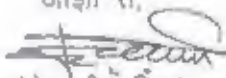
भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 452 (1)/XXVII(1)/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. प्रबन्धक निदेशक, पेयजल विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
- ✓ 8. एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त